दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आदेश सुरक्षित तिथि: 21 मार्च 2023
आदेश घोषित तिथि: 30 मई 2023

मू. वि. या. (निष्पा.प्र.अ.) (वाणि.) 11/2021
नुओवो पिग्नोन इंटरनेशनल एसआरएल

..... डिक्री धारक

द्वारा: श्री जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अभिज्नान झा, सुश्री भाग्य यादव, सुश्री साध्वी छाबड़ा और श्री श्रीकर, अधिवक्तागण

बनाम

कारगो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं
अन्य

..... निर्णीत ऋणी

द्वारा: श्री वरुण के. चोपड़ा, श्री आर. वी. प्रभात, सुश्री मेहूल शर्मा, श्री दीपू कुमार झा, अधिवक्तागण

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा

<u>आदेश</u>

<u>निष्पा.आ. (मूल पक्ष) 3525/2022 (निर्देश)</u>

1. वर्तमान आदेश के माध्यम से न्यायालय उन आपत्तियों का निपटान करने के लिए आगे बढ़ता है जो वर्तमान प्रवर्तन याचिका में प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। आईसीसी मध्यस्थता संख्या 24918/जीआर[1] में दिनांकित 05

अक्टूबर 2020 के विदेशी सहमति पंचाट को लागू करने के लिए याचिका को दर्ज की गई है। प्रवर्तन का प्रत्यर्थीगण द्वारा विरोध किया गया है, जो माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1962 की धारा 48 के संदर्भ में तर्क देते हैं कि सहमति पर पारित किया गया पंचाट ऐसा नहीं है जो विदेशी मध्यस्थता पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन के तहत लागू करने योग्य है। इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया है कि चूंकि अधिनिर्णय स्वयं आर्थिक विबाध्यता का परिणाम है और इसलिए भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है, इसलिए इसे 1996 के अधिनियम के तहत लागू करने में सक्षम नहीं माना जाना चाहिए। जो आपत्तियां उठाई गई हैं, उन पर निर्णय देने के प्रयोजन से निम्नलिखित आवश्यक तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है।

2. प्रवर्तन याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 ने 6.7 मिलियन यूरो के विचार के लिए स्टीम टर्बाइन जेनरेटर पैकेज की बिक्री के लिए एक उपकरण खरीद समझौते में प्रवेश किया, जो लगभग 60 करोड़ रुपये के बराबर है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रवर्तन याचिकाकर्ता के पक्ष में पैरेंट कंपनी गारंटी[5] निष्पादित की और दूसरे प्रत्यर्थी के लिए गारंटर की स्थिति में खड़ा हुआ जो उसकी सहायक कंपनी थी। कहा जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को 1,082,140 यूरो [लगभग 9.52 करोड़ रुपये] के बदले प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं को शामिल करने के लिए ईपीए में संशोधन किया गया है।]

3. पक्षकारगण के बीच उत्पन्न हुए विवादों और ईपीए का हिस्सा बनने वाले सामानों के संबंध में भुगतान करने में प्रत्यर्थीगण की ओर से विफलता के

परिणामस्वरूप, प्रवर्तन याचिकाकर्ता ने सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए रेफर करने का अनुरोध प्रस्तुत किया, जैसा कि ईपीए का खंड 26.2 के तहत विचार किया गया है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष होने वाली कार्यवाही को अंतिम अधिनिर्णय से एकत्रित किया जा सकता है जो प्रदान किया गया था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण अभिलेख करता है कि मध्यस्थता के लिए अनुरोध 22 नवंबर 2019 को आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय को प्राप्त हुआ था। आईसीसी सचिवालय ने 25 नवंबर 2019 को उस अनुरोध की प्राप्ति की पुष्टि की। 15 फरवरी 2020 को, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने आईसीसी सचिवालय को पुष्टि की कि उन्हें मामले में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिवत नियुक्त किया गया है और उन्होंने अपने अधिकार पत्र भी संलग्न किए हैं।

4. 18 फरवरी 2020 के संचार के संदर्भ में, आईसीसी सचिवालय ने प्रत्यर्थीगण से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन पर उनकी टिप्पणियां प्रदान करने का आह्वान किया। 19 फरवरी 2020 के अपने संचार के संदर्भ में, प्रत्यर्थीगण ने एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की और आईसीसी से आगे बढ़ने का अनुरोध किया। 26 मार्च 2020 को, पक्षकारगण को सूचित किया गया कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें अग्रिम भुगतान योग्य लागतों से भी अवगत कराया गया है। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में पक्षकारगण को 17 अप्रैल 2020 को सूचित किया गया था, जिसके बाद अभिलेख नामित मध्यस्थ को भेज दिए गए थे।

5. 23 अप्रैल 2020 को, माध्यस्थम् अधिकरण ने पक्षकारगण को संदर्भ की शर्तों के एक मसौदे के साथ-साथ उनकी टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए प्रक्रियात्मक समय सीमा और निर्देश भेजे दिए। दावे का विवरण उसके प्रदर्शनों के साथ 22 मई 2020 को दाखिल किया गया। प्रत्यर्थीगण ने 13 जुलाई 2020 को प्रदर्शनों के साथ अपने बचाव का बयान प्रस्तुत किया। 17 अगस्त 2020 को एक ईमेल द्वारा, दावेदार/प्रवर्तन याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण को सूचित किया गया कि पक्षकारगण ने विवाद में मामलों का निपटारा कर लिया है। नतीजतन, अधिकरण 20 अगस्त 2020 को पक्षकारगण को उनकी समीक्षा और टिप्पणियों के लिए एक मसौदा सहमति अधिनिर्णय अग्रेषित करने के लिए आगे बढ़ा।

6. बताया गया है कि प्रत्यर्थीगण और दावेदार दोनों ने दिनांक 01 सितंबर 2020 और 04 सितंबर 2020 को ईमेल के माध्यम से अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। अधिकरण ने विशेष रूप से दर्ज किया है कि प्रत्यर्थीगण ने दावेदार द्वारा किए गए इस अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी कि दिनांक 13.08.2020 के निपटान समझौते की एक विधिवत प्रमाणित प्रति को शामिल किया जाए और सहमति अधिनिर्णय का हिस्सा बनाया जाए। माध्यस्थम् अधिकरण ने यह भी दर्ज किया है कि 19 जून 2020 तक प्रत्यर्थीगण का प्रतिनिधित्व अधिवक्तागण के एक समूह द्वारा किया गया था जिनका विवरण अधिनिर्णय के अनुच्छेद 12 में दर्ज किया गया है। हालांकि, 19 जून 2020 के एक ईमेल द्वारा, खेतान एंड कंपनी के एक भागीदार ने प्रतिनिधित्व में बदलाव के बारे में माध्यस्थम्

अधिकरण को अवगत कराया। उपरोक्त के मद्देनजर, अधिकरण ने संदर्भ अभिलेखबद्ध की संशोधित शर्तों को जारी किया जो 23 जून 2020 को बदलती हैं और उन संशोधित शर्तों पर 26 जून 2020 को प्रवर्तन याचिकाकर्ता और 29 जून 2020 को प्रत्यर्थीगण द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे।

7. परिणामस्वरूप अधिकरण निम्नलिखित शर्तों में सहमति अधिनिर्णय तैयार करने के लिए आगे बढ़ाः-

> —48. सहमति से इस अधिनिर्णय द्वारा:
>
> क. मध्यस्थता में किए गए सभी दावों को दावेदार, प्रथम प्रत्यर्थी और द्वितीय प्रत्यर्थी के बीच 13 अगस्त 2020 को किए गए निपटान समझौते में निर्धारित शर्तों पर वापस लिया जाता है, जिसकी एक प्रति यहां संलग्न की गई है और अधिकरण (**"निपटान समझौता"**) द्वारा आरंभ की गई है।
>
> ख. अधिकरण निपटान समझौते को एक अधिनिर्णय की शक्ति और आदेश और निर्देश देता है कि उसके पक्ष इसकी शर्तों का पालन करें।
>
> ग. प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता के संबंध में किए गए अपने खर्चों को स्वयं वहन करेगा।
>
> घ. आईसीसी की लागत और न्यायालय द्वारा निर्धारित मध्यस्थ की फीस का भुगतान लागत पर अग्रिम से किया जाएगा। कोई भी शेष राशि दावेदार को वापस कर दी जाएगी।
>
> ड. आईसीसी नियमों के परिशिष्ट III अनुच्छेद 2 (13) के अनुसार मध्यस्थों के शुल्क पर वैट के भुगतान के लिए पक्ष संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

8. अभिलेख की पूर्णता के लिए, न्यायालय निपटान समझौते के निम्नलिखित मुख्य प्रावधानों को उद्धृत करना भी उचित समझता हैः-

2.1 पक्षकारगण एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं कि कार्गो सोलर पर ईपीए और अनुबंध संशोधन के तहत €1.587.140 और भंडारण और संरक्षण लागत ("बकाया राशि") के रूप में €400.000 बकाया है।

2.2 कार्गो सोलर निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार 13 **लाख यूरो** ("निपटान राशि") का भुगतान करेगाः

अनुसूची	भुगतान की तिथि	राशि
माइलस्टोन 1	7 सितंबर 2020	€337,250
माइलस्टोन 2	7 दिसंबर 2020	€337,250
माइलस्टोन 3	7 मार्च 2020	€312,750
माइलस्टोन 4	7 जून 2021	€312,750
		€1,300,000

2.4 यदि कार्गो सोलर इस खंड 2 के अनुसार निपटान राशि का भुगतान करता है, तो एनपी ईपीए और अनुबंध संशोधन के तहत शेष € 287,140 और बकाया राशि के भंडारण और संरक्षण लागत के रूप में € 400,000 का अपना अधिकार स्वीकार कर लेगा। खंड 2.2 के तहत अनुसूची के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने पर, कार्गो सोलर और कार्गो मोटर को इस निपटान समझौते के तहत अपने दायित्वों को विधिवत पूरा करने वाला माना जाएगा और एनपी नीचे खंड 3 के अनुसार कार्गो को एसटीजी पैकेज वितरित करेगा।

3.1 एन.पी.:

(क) 30 जून 2021 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एसटीजी पैकेज को स्टोर और संरक्षित करेगा; और

(ख) ईपीए के खंड 9 और अनुबंध I के अनुसार एसटीजी पैकेज वितरित करेगा, जिसे इस निपटान समझौते में यथोचित परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया है।

3.2 कार्गो सोलर ई. पी. ए. के खंड 11 के अनुसार 30 जून 2021 तक एस. टी. जी. पैकेज की पिक-अप और एफ. ओ. बी. डिलीवरी की व्यवस्था करेगा, *जिसे एतद्द्वारा* इस निपटान समझौते में यथोचित परिवर्तन को शामिल किया गया है।

6.2 संदेह से बचने के लिए।

क. कार्गो सोलर के प्रदर्शन में कोई भी देरी उपरोक्त खंड 2 में भुगतान अनुसूची में निर्धारित भुगतान तिथियों को विस्तारित, विलंबित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी; और

ख. खंड 6.1 कार्गो सोलर को इस निपटान समझौते के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी उल्लंघनों को दूर करने के लिए कुल 45 (पैंतालीस) कैलेंडर दिनों का अधिकार देता है, खंड 6.1 कार्गो सोलर को गैर-प्रदर्शन के प्रत्येक उदाहरण के लिए 45 (पैंतालीस) कैलेंडर दिनों की अवधि प्रदान नहीं करता है।

6.3 यदि कार्गो सोलर इस खंड 6 के अनुसार अपने गैर-प्रदर्शन को ठीक नहीं करता है, तोः

(क) पूरी बकाया राशि (निपटान समझौते के तहत पहले से भुगतान की गई किसी भी राशि से कम) तुरंत देय और देय हो जाएगी, जिसमें उस पर ब्याज भी शामिल होगा।
(ख) एन. पी. इस तह के गैर-प्रदर्शन की तारीख से 9 (नौ) महीनों के भीतर या 30 जून 2022 को, जो भी पहले हो, आवश्यकतानुसार एस. टी. जी. पैकेज का निपटान कर सकता है; और
(ग) एन. पी. आवश्यकतानुसार और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त अधिकार क्षेत्र के स्थानीय न्यायालयों में इस

निपटान समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए परिशिष्ट ए में निर्धारित सहमति आदेश प्राप्त कर सकता है।

6.4 इस निपटान समझौते के तहत कार्गो सोलर के दायित्वों का निर्वहन, विलंब, माफ़ी या अन्यथा प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(क) इस निपटान समझौते के शासकीय कानून के तहत उत्पन्न होने वाली कोई अप्रत्याशित घटना;
(ख) कार्गो सोलर और/या कार्गो मोटर्स की स्थिति का कोई पुनर्गठन या परिवर्तन;
(ग) दिवाला, दिवालियापन, समापन, परिसमापन, या कार्गो सोलर और/या कार्गो मोटर्स, उनके उपक्रमों, और/या उनकी संपत्तियों का विघटन;
(घ) कार्गो सोलर और/या कार्गो मोटर्स के रिसीवर, प्रशासक, ट्रस्टी या इसी तरह के अधिकारी की नियुक्ति, उनके उपक्रम, और / या उनकी संपत्तियों;
(ङ) कोई कार्य, चूक, घटना या परिस्थितियाँ जो (इस प्रावधान के अलावा) किसी प्रतिभूति या गारंटर के लिए या छूट कानूनी या न्यायसंगत बचाव का गठन करेगा या कर सकता है; या
(च) या कोई अन्य समान घटना।

7.1 कार्गो मोटर्स की देनदारियां और दायित्व पीसीजी की शर्तों के अधीन होंगे, जिसे इस निपटान समझौते में यथोचित परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया है।

11.2. संयुक्त रूप से अनुरोध करने पर कि इस निपटान समझौते को एक मध्यस्थता अधिनिर्णय में शामिल किया जाए, पार्टियां प्रतिनिधित्व करती हैं कि उन्हें:

(क) इस मामले पर भारतीय कानून पर स्वतंत्र कानूनी सलाह सहित स्वतंत्र कानूनी सलाह प्राप्त हुई है। उस आधार पर, पक्षकारगण आगे स्वीकार करते हैं कि मध्यस्थता अधिनिर्णय भारतीय न्यायालय में अपनी शर्तों पर लागू करने योग्य है। पार्टियां आगे इस बात पर सहमत हैं कि निर्णय को लागू करने

से इनकार करने का कोई आधार नहीं है, चाहे वह (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 48 के तहत हो या किसी अन्य कानून के तहत। कार्गो सोलर और कार्गो मोटर्स निर्णय की एक प्रति प्राप्त होने पर और बिना किसी देरी के तुरंत पुरस्कार का भुगतान करने का वचन देते हैं। और किसी भी प्रवर्तन कार्रवाई की आवश्यकता है; और

(ख) बिना किसी आपत्ति के निर्णय का भुगतान करने के लिए कार्गो सोलर और कार्गो मोटर्स के दायित्व को कम किए बिना, एनपी भारत में इस निर्णय की मान्यता और प्रवर्तन के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय से संपर्क करने का हकदार होगा। एनपी कार्गो सोलर और कार्गो को पूर्व सूचना के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी| कार्गो सोलर और कार्गो मोटर्स तुरंत मामले में उपस्थित होंगे और बिना किसी बचाव का हवाला दिए निर्णय की मान्यता और प्रवर्तन को स्वीकार करेंगे।

15.1. यह समझौता समझौता मध्यस्थता के निपटान के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौते को निर्धारित करता है।

15.2 प्रत्येक पक्ष ने इस निपटान समझौते के प्रारूपण और बातचीत में भाग लिया है तदनुसार, इस निपटान समझौते को पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया माना जाएगा जो पारस्परिक रूप से घोषणा करते हैं कि संविदात्मक प्रावधान उनकी सच्ची इच्छा की सभी अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

9. वर्तमान प्रवर्तन याचिका इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई है जिसमें निपटान समझौते के तहत परिकल्पित निपटान राशि को पूरा करने के लिए प्रत्यर्थीगण की ओर से गैर-अनुपालन का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन

याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थीगण कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और उन्होंने अधिनिर्णय को लागू करने की मांग की है।

10. प्रत्यर्थीगण ने सबसे पहले अधिनिर्णय की मान्यता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चूंकि यह एक था जो सहमति पर प्रदान किया गया था, इसलिए यह सम्मेलन के तहत मान्यता प्राप्त अधिनिर्णयों के दायरे में नहीं आएगा। यह उपरोक्त आपत्ति थी जिसका मुख्य रूप से इस न्यायालय के समक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन "व्यक्तियों के बीच *मतभेदों से उत्पन्न होने वाले" अधिनिर्णयों* की मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित है। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि न्यूयॉर्क कन्वेंशन समझौते पर दिए गए अधिनिर्णयों पर विचार नहीं करता है, इसलिए प्रवर्तन कार्रवाई कायम नहीं रहेगी। विद्वान अधिवक्ता ने कुछ प्रारंभिक सामग्री का भी उल्लेख किया था जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के औपचारिकरण से पहले प्रस्तुत करने के लिए थी कि विभिन्न देशों ने सहमति और समझौते को शामिल करके अधिनिर्णयों के लिए विशिष्ट अनुरोध किए थे। हालाँकि, यह तर्क दिया गया कि जब न्यूयॉर्क कन्वेंशन अंततः घोषित किया गया, तो निपटान अधिनिर्णय स्पष्ट रूप से शामिल नहीं थे। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह परिस्थिति स्पष्ट रूप से सुझाव देगी कि निपटान अधिनिर्णय कन्वेंशन के तहत नहीं आते हैं। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण पूर्ववर्ती संघीय गणराज्य जर्मनी के साथ-साथ ऑस्ट्रिया द्वारा और उसकी ओर से किए गए कुछ अभ्यावेदनों के आधार पर आगे बढ़ता है। यह उनके अभ्यावेदन के उद्धरणों से स्पष्ट होगा जैसा कि

महासचिव की दिनांक 31 जनवरी 1956 की रिपोर्ट में शामिल है। उस रिपोर्ट के प्रासंगिक हिस्से यहां नीचे प्रस्तुत किए गए हैं: -

> **—जर्मनी का संघीय गणराज्य**
>
> ""सम्मेलन के दायरे को विस्तारित करने के विचार पर भी विचार किया जाना चाहिए, जिसमें अधिनिर्णय के अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों के समक्ष हुए समझौते भी शामिल हों। जिस समय जिनेवा कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था उस समय यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे समझोतों से जुड़े प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाएगा; ऐसे प्रावधान की अनुपस्थिति अक्सर व्यवहार में एक खेदजनक चूक साबित हुई है। इसलिए, यह सुझाव देना उचित है कि इस अंतर को अब समाप्त किया जाना चाहिए।"
>
> **ऑस्ट्रिया**
>
> "सम्मेलन को शायद मध्यस्थ निपटानों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए। उस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए; यह ऑस्ट्रियन अभ्यास (न्यायिक निर्णयों के प्रवर्तन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुच्छेद 1, पंक्ति 16) को ध्यान में रखते हुए होगा क्योंकि निर्णयों की वैधता का परीक्षण करने के अवसर पर्याप्त हैं और प्रवर्तन से इनकार करने के आधार पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे प्रावधान पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।"

11. निवेदन अनिवार्य रूप से यह था कि चूंकि मध्यस्थता समझौतों को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क कन्वेंशन की शर्तों के विस्तार का अनुरोध कभी भी विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया था, इसलिए सहमति अधिनिर्णयों को न्यूयॉर्क समझौते के दायरे और सीमा से बाहर होने के रूप में समझा जाना चाहिए।

12. जहां तक आर्थिक विबाध्यता के मुद्दे का सवाल है, यह विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि प्रवर्तन याचिकाकर्ता द्वारा निपटान की शर्तों को उस अवधि के दौरान जल्दबाजी में आगे बढ़ाया गया जब महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और उचित कानूनी राय लेने से प्रत्यर्थीगण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थीगण को सहमति की शर्तों से सहमत होने के लिए मजबूर किया गया था, भले ही निपटान समझौते को पढ़ने से यह साबित हो जाएगा कि यह स्पष्ट रूप से केवल प्रवर्तन याचिकाकर्ता के पक्ष में संचालित करने के लिए तैयार किया गया है।

13. श्री जयंत मेहता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो प्रवर्तन याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए और निम्नलिखित प्रस्तुतियों को संबोधित किया, ने उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध किया। श्री मेहता ने तर्क दिया कि सम्मेलन *"अधिनिर्णयों"* को बिल्कुल भी परिभाषित नहीं करता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, केवल इसलिए कि संघीय गणराज्य जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अभ्यावेदन अंततः कन्वेंशन में शामिल किए जा रहे निपटानों के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों में परिवर्तित नहीं हुए, यह किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं ले जा सकता है कि निपटान पर अधिनिर्णय इसके तहत लागू नहीं होंगे।

14. श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि यह आपत्ति कि विदेशी सहमति अधिनिर्णयों को लागू नहीं किया जा सकता है या मान्यता प्राप्त नहीं है, एक ऐसी दलील है जिसे हरेंद्र एच. मेहता बनाम मुकेश एच. मेहता में उच्चतम

न्यायालय ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया था। यह बताया गया कि यद्यपि उपरोक्त निर्णय विदेशी अधिनिर्णय (विनियमन और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन उसमें निर्धारित सिद्धांत स्पष्ट रूप से लागू होंगे। श्री मेहता ने रिपोर्ट के अनुच्छेद 22 और 23 का उल्लेख किया जो नीचे दिया गया है: -

> **"22.** हमें समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे कहा जा सकता है कि यह अधिनिर्णय विदेशी अधिनिर्णय नहीं था। विदेशी अधिनिर्णय की सभी सामग्री वहाँ थी। दोनों पक्षों का भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में एक संयुक्त उद्यम के रूप में व्यवसाय था और उन्होंने संपत्तियों का अधिग्रहण भी किया। पक्षों के बीच जो मतभेद उत्पन्न हुए वे कानूनी संबंधों से बाहर थे और निश्चित रूप से इस देश के कानूनों के तहत वाणिज्यिक प्रकृति के थे। विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का समझौता, लिखित रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था जहां मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की गई थी और अधिनिर्णय दिया गया था। यह विवादित नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका *एक* ऐसा देश है जिस पर विदेशी अधिनिर्णय अधिनियम की धारा 2 का खंड (ख) लागू होता है। वर्तमान मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पक्ष एक-दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन वे विदेशी अधिनिर्णय अधिनियम के दायरे से बाहर अधिनिर्णय नहीं ले सकते हैं। हमने श्री गणेश से पूछा कि क्या होगा यदि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में दो अजनबियों का व्यवसाय है या एक भारतीय और एक अमेरिकी नागरिक के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसके पास दोनों देशों में चल और अचल दोनों संपत्तियां हैं और संयुक्त राज्य में विवाद उत्पन्न हुए हैं और अधिनिर्णय दिए गए हैं। श्री गणेश अपनी कुशलता के बावजूद कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। अपीलार्थी की आपत्ति में कोई योग्यता नहीं है कि अधिनिर्णय विदेशी अधिनिर्णय नहीं है और यह विदेशी अधिनिर्णय अधिनियम के बाहर है।

23. यह कि अधिनिर्णय एक मध्यस्थता अधिनिर्णय नहीं है, श्री गणेश का निवेदन था कि मध्यस्थता समझौता जो 17-11-1989 पर किया गया था, पक्षों द्वारा दिनांकित 20-3-1990 के निपटान समझौते पर पहुंचने के बाद रद्द कर दिया गया था। विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए पूर्व समझौते दिनांकित 25-10-1989 को दिनांकित 17-11-1989 समझौते द्वारा निरस्त कर दिया गया था। श्री गणेश ने निपटान समझौते की शर्तों को विस्तार से पढा ताकि यह तर्क दिया जा सके कि पक्षों ने स्वयं अपने विवादों का समाधान कर लिया है और यह समझौता इस तथ्य की परवाह किए बिना प्रभावी होना था कि क्या मध्यस्थ ने उसके संदर्भ में अपना निर्णय दिया है या नहीं। उन्होंने कहा कि पक्षकारों द्वारा अपने व्यवसायों और संपत्तियों वाले विभिन्न पैकेजों का विकल्प चुनने के बाद मध्यस्थ को केवल एक रबर स्टाम्प के रूप में व्यवहार करना था। संक्षेप में प्रस्तुतिकरण यह था कि जब तक कोई विवाद या मतभेद नहीं होता, तब तक कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती। पक्षकारगण के बीच दिनांक 17-11-1989 को हुए समझौते के बाद मध्यस्थ को न केवल न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता थी, बल्कि, वास्तव में, उसे न्यायिक रूप से कार्य करने और पक्षकारगण के अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय देने से रोका गया था। उससे यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह सुनेगा या अपना दिमाग लगाएगा या कोई मध्यस्थता कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में, भले ही एक मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में था, जिसे एक बुनियादी और सरल कारण से रद्द कर दिया गया था कि उस समय कोई विवाद मौजूद नहीं था। समझौता सीधे अधिनिर्णय में कर दिया गया। अपनी दलीलों के समर्थन में, श्री गणेश ने के.के. मोदी बनाम के.एन. मोदी [(1998) 3 एससीसी 573] में इस न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी व्यक्ति को पक्षकारगण के बीच एक निश्चित विवाद का निर्णय करने के लिए अधिकृत किया गया है लेकिन उसके पास मध्यस्थ के रूप में करने के लिए कोई कार्य नहीं है, वह कोई अधिनिर्णय नहीं दे सकता। लेकिन उस मामले में, पक्षकारगण के बीच समझौता ज्ञापन के खंड (9) के तहत अलग-अलग तर्क थे: एक का तर्क था कि खंड

मध्यस्थता समझौते का गठन करता है, दूसरे का इसके विपरीत तर्क था। यह खंड (9) इस प्रकार था: (एससीसी पृष्ठ 580, पैरा 3)

"कार्यान्वयन वित्तीय संस्थानों के परामर्श से किया जाएगा। इस समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में सभी विवादों, स्पष्टीकरणों आदि के लिए, इसे अध्यक्ष, आईएफसीआई या उनके नामांकित व्यक्तियों को भेजा जाएगा जिनके निर्णय अंतिम और दोनों समूहों के लिए बाध्यकारी होंगे।"

इस संदर्भ में इस न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष, आईएफसीआई द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की प्रकृति को देखते हुए, उनका निर्णय मध्यस्थता अधिनिर्णय नहीं है। इस निर्णय से श्री गणेश को अपनी दलीलों में शायद ही कोई मदद मिले। वर्तमान मामले में, पक्षकारों ने मध्यस्थता कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान समझौता किया। अपीलार्थी ने स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया और कभी शिकायत नहीं की कि यह एक अधिनिर्णय नहीं था। सीपीएलआर 7507 और सीपीएलआर 7510 के तहत कार्यवाही में, हरेंद्र ने निपटान समझौते के निष्पादन और मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को भी स्वीकार कर लिया था। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय में या इस न्यायालय में अपील के आधार पर ऐसी कोई याचिका नहीं ली गई थी। नासाउ काउंटी न्यायालय ने निपटान समझौते में मध्यस्थ द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान दिया। हम श्री गणेश के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि मध्यस्थता समझौते को तब रद्द कर दिया गया था जब मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकारों ने आपस में समझौता किया था और फिर भी चाहते थे कि मध्यस्थ उसके संदर्भ में अपना निर्णय दे। यह किसी का मामला नहीं है कि मध्यस्थ के अधिकार को किसी भी समय रद्द कर दिया गया था। श्री गणेश का यह तर्क हमें महज हताशा में दिया गया प्रतीत होता है।

15. इसके बाद श्री मेहता ने एल्बटेलेकॉम एसएच ए. बनाम यूएनआईएफआई कम्युनिकेशंस मामले में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की ओर न्यायालय का

ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ-साथ गिनी VII लिमिटेड की ट्रांसओसियन ऑफशोर बनाम एरिन एनर्जी कॉर्पोरेशन में टेक्सास के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय की तरफ तर्क के लिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायालयों ने समान याचिकाओं को खारिज कर दिया है। एल्बटेलेकॉम में निर्णय के माध्यम से न्यायालय को आगे बढ़ाते हुए, श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि जिला न्यायालय एक विदेशी मध्यस्थता अधिनिर्णय की पुष्टि के लिए एक याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान पक्षकारगण के बीच हुए समझौते की शर्तों को शामिल किया गया था। उस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी ने आपत्ति जताई थी कि कन्वेंशन लागू नहीं होगा क्योंकि अधिनिर्णय ने सहमति अधिनिर्णय का रूप ले लिया है। श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि उक्त आपत्ति को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया है जैसा कि उस निर्णय के निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट होगा: -

> **"ख. विश्लेषण**
>
> अल्ब्टेलकॉम सबसे पहले न्यायालय से अधिनिर्णय की पुष्टि करने के लिए कहता है। अधिनिर्णय की अपनी समीक्षा और पक्षों की प्रस्तुतियों के आधार पर, और यहां उपयुक्त सीमित समीक्षा करने के बाद, न्यायालय इस बात से सहमत है कि पुष्टि के रूप में विचारण के लिए तथ्य का कोई भौतिक मुद्दा नहीं है, और यह कि अधिनिर्णय ठीक से दर्ज किया गया था। अधिनिर्णय का स्वरूप मध्यस्थता प्रक्रिया में दोनों पक्षों की पूर्ण भागीदारी को दर्शाता है, जो अधिनिर्णय दर्ज करने की तारीख तक तीन साल से अधिक समय तक आगे बढ़ी थी। अधिनिर्णय दोनों पक्षों द्वारा अधिनिर्णय की शर्तों और व्याख्यान पर सहमति दर्शाता है। यह मध्यस्थ नॉल द्वारा उचित देखभाल को दर्शाता है। और अधिनिर्णय के लिए पक्षकारगण की

सहमति - इसकी शर्तों के लिए उनकी शर्त - इसके प्रवेश के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है।

पुष्टि के खिलाफ यूनिफी का एकमात्र तर्क यह है कि अधिनिर्णय पक्षकारों की सहमति से दिया गया था, जबकि यह तथ्यात्मक और कानूनी विवादों के मध्यस्थ के समाधान पर आधारित था। यूनिफी का दावा है कि "पक्षकरगण मध्यस्थता के बाहर अपने विवाद को निपटाने के लिए सहमत हुए"। यूनिफी ज्ञापन (एमईएम)13 पर। लेकिन यह गलत है। यहाँ के पक्ष निश्चित रूप से एक निजी निपटान समझौते के पक्ष में मध्यस्थता को खारिज कर सकते थे।

इसके बजाय, जैसा कि ऊपर समीक्षा किए गए अभिलेख से पता चलता है, उन्होंने सकारात्मक रूप से मध्यस्थ नॉल को आई*सीसी मध्यस्थता* अधिनिर्णय के हिस्से के रूप में, शब्दशः, अधिनिर्णय में अपने निपटान समझौते की शर्तों को अपनाने के लिए कहा। इसके बाद पक्षकारगण मध्यस्थ की सहमति से मसौदा अधिनिर्णय को संपादित करने के लिए आगे बढ़े, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उनके *समझौते* को दर्शाता है। इसलिए, पक्षकारगण के विवाद को "मध्यस्थता के बाहर" हल करने की जगह, अंततः मध्यस्थता में हल किया गया, जो पक्षकारगण की विशेष शर्तों के लिए शर्त के आधार पर था जैसा कि अधिनिर्णय में सन्निहित है।

यूनिफी ने इस प्रभाव के लिए किसी भी कानून का हवाला नहीं दिया है कि अधिनिर्णय एक आईसीसी मध्यस्थ, मध्य-मध्यस्थता, पक्षों की सहमति से और पक्षों द्वारा सहमत शर्तों के आधार पर, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत अधिक विवादास्पद मुकदमेबाजी के बाद दर्ज किए गए आईसीसी अधिनिर्णय की तुलना में कम बाध्यकारी है। इस तरह के अपवाद का कोई कारण नहीं है। इसके विपरीत, विपरीत नियम मध्य-मध्यस्थता में विवादों के समाधान को हतोत्साहित करेगा। आईसीसी के तहत मध्यस्थता शुरू करने वाले पक्ष समझौता करने के लिए कम इच्छुक हो सकते हैं, एक समझौते का

निहितार्थ था कि परिणामी अधिनिर्णय न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत अपनी प्रवर्तनीयता खो देगा। इस मुद्दे पर वास्तव में सीमित कानून है, संभवतः इसलिए कि पक्षों की सहमति के बाद प्राप्त किए गए अधिनिर्णयों के बाद के विवादों में परिणत होने की संभावना कम है लेकिन सीमित उपलब्ध उदाहरण पक्षों द्वारा पूर्व निर्णय के *आधार पर किए गए अधिनिर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन को दर्शाते हैं। देखें, उदाहरण के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स बनाम स्पेरी कॉर्पोरेशन, 493 यू.एस. 52,56-57,110 एस. सी. टी. 387,107 एल. ईडी. 2डी 290 (1989);* बेकर्स *यूनियन फैक्ट्री, #326 बनाम आई. टी. टी. कॉन्टिनेंटल बेकिंग कंपनी,आईएनसी, 749 एफ. 2डी 350,354 (छठा सीआईआर* 1984); *ब्रूस हार्डवुड फ्लोर बनाम एस. काउंसिल ऑफ इंडस. वर्कर्स, 8 एफ.3डी 1104, 1107 (6वां सर्कुलर 1993); वॉस स्टील कर्मचारी संघ बनाम वॉस स्टील कार्पोरेशन, 797 एफ. सप्लिमेंट। 585, 590 (ए.फडी. मिशिगन 1992), एफ़एड, 16 एफ.3डी 1223 (6वां सर्कुलर 1994)।*

इसलिए न्यायालय मध्यस्थता अधिनिर्णय की पुष्टि करेगा। न्यायालय निर्णय में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्णय दर्ज करने का आदेश देगा जानने के लिए कि, 2 सितंबर, 2015 तक यूनिफी को 39 मासिक किश्तों का भुगतान पूरी तरह से ईयूआर 1,088,000 की करने की आवश्यकता थी, अधिनिर्णय में दर्शाई गई राशि और तिथियों में, और अधिनिर्णय में परिलक्षित अन्य दायित्वों का पालन करने के लिए।॥

16. श्री मेहता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अल्बटेलकॉम में वर्णित कानूनी स्थिति को *ट्रांसओसियन* में दोहराया गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता *ने* उपरोक्त निर्णय से निम्नलिखित अंशों का उल्लेख कियाः-

"मध्यस्थता अधिनिर्णय की पुष्टि के खिलाफ एरिन एनर्जी का एकमात्र तर्क यह है कि यह एक "सहमति अधिनिर्णय" है और इसलिए कन्वेंशन के अधीन नहीं है। एरिन एनर्जी ने निष्कर्ष निकाला कि याचिका को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायालय के पास विषय-वस्तु

अधिकार क्षेत्र का अभाव है। (डॉकेट प्रविष्टि संख्या 28)। मामला कानून का हवाला देने के बदले एरिन एनर्जी ने कन्वेंशन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून सचिवालय गाइड पर 2016 संयुक्त राष्ट्र आयोग का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि न तो कन्वेंशन और न ही रिपोर्ट किया गया मामला कानून विशेष रूप से सहमति अधिनिर्णयों आईडी 2 को संबोधित करता है। अब *ऐसा* नहीं है।

2017 में, समान तथ्यों और कानूनी मुद्दों वाले एक मामले में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले ने ऐसा किया कि एक अधिनिर्णय "तथ्यात्मक और कानूनी विवादों के मध्यस्थ के समाधान पर आधारित होने के विपरीत, पक्षकारगण की सहमति से दिया गया", कन्वेंशन एल्बटेलेकॉम एसएच.ए बनाम यूएनआईएफआई कम्युनिकेशंस, इंक, 2017 यूएस डिस्ट्रिक्ट लेक्सिस 82154, 2017 डब्ल्यूएल 2364365, *5 मामले में (एस.डी.एन.वाइ. 30 मई, 2017) द्वारा कवर किया गया और इसके अधीन है। अल्बटेलेकॉम में याचिकाकर्ता ने इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के मध्यस्थ द्वारा तय किए गए एक मध्यस्थ अधिनिर्णय की पुष्टि की मांग की। यह अधिनिर्णय पक्षकारगण की सहमति 2017 यूएस डिस्ट्रिक्ट लेक्सिस 82154, [डब्ल्यूएल] *1 पर आधारित था। पुष्टि के खिलाफ प्रतिवादी का "एकमात्र तर्क" यह था कि अधिनिर्णय पक्षकारों की सहमति से दिया गया था, जिस पर प्रतिवादी ने दावा किया कि पक्षकारों ने अपने विवाद को "मध्यस्थता के बाहर" 2017 यूएस डिस्ट्रिक्ट लेक्सिस 82154, [डब्ल्यूएल] *5 पर सुलझा लिया था। *अल्बटेलकॉम* न्यायालय को दो *कारणों* से असहमत थी। सबसे पहले, हालांकि पक्षकार एक निजी निपटान समझौते को आगे बढ़ाने के लिए मध्यस्थता को खारिज कर सकते थे, उन्होंने इसके बजाय "सकारात्मक रूप से [मध्यस्थ] को मध्यस्थता अधिनिर्णय के हिस्से के रूप में शब्दशः, अधिनिर्णय में उनके निपटान समझौते की शर्तें को अपनाने के लिए कहा. आईडी. दूसरा, *प्रत्यर्थी* ने किसी सहमति अधिनिर्णय को कन्वेंशन के बाहर मानने का समर्थन करने के लिए किसी भी मामले के कानून का हवाला नहीं दिया,

या अधिकरण द्वारा एक न्यायिक कार्यवाही द्वारा से दर्ज किए गए अधिनिर्णय की तुलना में कम रोकने या प्रवर्तनीयता का हकदार है, *भले* ही पक्ष परिणाम से सहमत न हों। आईडी. जैसा कि न्यायालय ने समझायाः

> ऐसे अपवाद का कोई कारण नहीं है। इसके विपरीत, विपरीत नियम मध्य मध्यस्थता में विवादों के समाधान को हतोत्साहित करेगा। जो पक्ष [मध्यस्थ न्यायालय] के तहत मध्यस्थता शुरू करते हैं, वे समझौता करने के लिए कम इच्छुक हो सकते हैं, समझौते का निहितार्थ यह था कि परिणामी अधिनिर्णय न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत अपनी प्रवर्तनीयता खो देगा। इस बिंदु पर वास्तव में सीमित कानून है, शायद इसलिए क्योंकि पक्षकारगण की सहमति के बाद प्राप्त अधिनिर्णयों के परिणामस्वरूप बाद में विवाद होने की संभावना कम होती है। लेकिन सीमित उपलब्ध मिसालें पक्षकारगण की शर्तों के आधार पर दिए गए अधिनिर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन को दर्शाती हैं।
>
> आईडी.

अल्बटेलीकॉम में विश्लेषण गहन और प्रेरक है। यह न्यायालय भी इसी नतीजे पर पहुंचती है। इस मामले में पक्षकारगण ने मध्यस्थता को खारिज नहीं किया। बल्कि, उन्होंने अपने स्वयं के समझौते पर आने के बाद भी मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने का विकल्प चुना। हालाँकि न्यायाधिकरण कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सका या कानूनी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सका, उसने एक निर्णय दिया जिसने पक्षकारगण को उसकी शक्ति के भीतर बाध्य कर दिया। (डॉकेट एंट्री नंबर 25-1 7-9 पर)। किसी भी बाध्यकारी या प्रेरक वैधानिक भाषा या मामले के कानून के लिए न्यायालय को यह मानने की आवश्यकता नहीं है कि एक न्यायाधिकरण को कन्वेंशन के अधीन एक वैध, बाध्यकारी अधिनिर्णय देने के लिए पक्षकारगण के समझौते से अलग

अपने निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। जैसा कि अल्बटेलेकॉम न्यायालय ने कहा, यह नियम पक्षकारगण को पहली बार में मध्यस्थता की मांग करने या इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली दक्षताओं से लाभ उठाने से रोक देगा।

एरिन एनर्जी लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नियमों का हवाला देती है, लेकिन वे उसके तर्क को कमज़ोर करते हैं, मज़बूत नहीं। नियम 26.2 में कहा गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया "कोई भी अधिनिर्णय" लिखित रूप में होना चाहिए" और, जब तक कि सभी पक्ष अन्यथा लिखित रूप में सहमत न हों, उन्हें उन कारणों का उल्लेख करना होगा जिन पर यह अधिनिर्णय आधारित है।" (डॉकेट प्रविष्टि संख्या 28 पर 3 (जोर दिया गया))। नियम 26.9 में कहा गया है कि सहमति अधिनिर्णय में "कारण शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।" आईडी एरिन एनर्जी का तर्क है कि एक "अधिनिर्णय" सहमति अधिनिर्णय नहीं हो सकता क्योंकि नियम 26.2 के तहत किसी भी अधिनिर्णय के लिए कारण शामिल होने की आवश्यकता होती है और नियम 26.9 बिना किसी कारण के सहमति अधिनिर्णय की अनुमति देता है। लेकिन एरिन एनर्जी नियम 26.2 और नियम 26.9 के पाठ में विराम चिह्नों को नजरअंदाज करती है। नियम 26.2 में "जब तक कि सभी पक्ष अन्यथा लिखित रूप में सहमत न हों" सहमति अधिनिर्णयों को संदर्भित करता है, जिसकी पुष्टि नियम 29.2 में प्रक्रिया द्वारा की जाती है। "पक्षों के विवाद के किसी भी अंतिम निपटान की स्थिति में, यदि *पक्ष संयुक्त रूप से लिखित रूप में अनुरोध करते हैं*, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण निपटान को रिकॉर्ड करते हुए एक अधिनिर्णय देने का निर्णय ले सकता है..." आईडी (महत्व जोड़ें)। नियम 26.2, दूसरे शब्दों में, कहता है कि सहमति अधिनिर्णय को छोड़कर सभी अधिनिर्णय में उन कारणों का उल्लेख होना चाहिए जिन पर अधिनिर्णय आधारित है। नियम सहमति अधिनिर्णय और अन्य मध्यस्थ अधिनिर्णय के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं।

चूँकि लंडन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन द्वारा दिया गया सहमति अधिनिर्णय कन्वेंशन के अधीन है, इसलिए इस मामले में मध्यस्थता

अधिनिर्णयों की पुष्टि *करने के लिए इस* न्यायालय के पास 9 यू. एस. सी. § 203 के तहत विषय-वस्तु अधिकार क्षेत्र है।"

17. तब यह दलील दी गई कि आर्थिक विबाध्यता पर आधारित आपत्ति न केवल गलत है बल्कि स्पष्ट रूप से अभिलेख के विपरीत है। श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि, निर्विवाद रूप से, प्रत्यर्थीगण को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के सभी चरणों में अधिवक्तागण द्वारा उचित रूप से प्रतिनिधित्व किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने स्वयं और निपटान समझौते की प्राप्ति पर पक्षकारगण के विचार के लिए एक मसौदा अधिनिर्णय परिचालित किया था और जिसके जवाब में प्रत्यर्थीगण ने किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। न्यायालय का ध्यान निपटान समझौते में दिखाई देने वाले विशिष्ट विवरणों की ओर भी आकर्षित किया गया था और खंड 11.2 में कहा गया है कि पक्षकारगण ने स्पष्ट रूप से और स्पष्ट शब्दों में निपटान समझौते को एक मध्यस्थ अधिनिर्णय में शामिल करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। यह भी बताया गया कि खंड 11.2 (क) आगे दर्ज करता है कि पक्षकारगण को इस मामले पर स्वतंत्र कानूनी सलाह प्राप्त हुई थी जिसमें भारतीय कानून के तहत प्राप्त होने वाली स्थिति के संबंध में सलाह भी शामिल थी। श्री मेहता ने खंड 11.2 (क) पर विशेष रूप से पक्षकारों को यह स्वीकार करते हुए अभिलेख करने पर जोर दिया कि अंतिम अधिनिर्णय अपनी शर्तों पर लागू होगा और यह 1996 अधिनियम की धारा 48 के उल्लंघन में नहीं आएगा।

इसके बाद श्री मेहता ने न्यायालय को निपटान समझौते के खंड 15.1 और 15.2 और उसमें दिखाई देने वाले विवरणों के बारे में बताया और जो स्पष्ट रूप से संबंधित पक्षों की समझ को दर्ज करने के लिए हैं कि वही संपूर्ण समझौते का गठन करता है और दोनों पक्षों ने भी इसे मान्यता दी और स्वीकार किया था और उचित बातचीत के बाद निपटान समझौते की तथ्यात्मक स्थिति पर पहुंचा गया है और अंततः दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से मसौदा तैयार किया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर, श्री मेहता का कहना था कि आर्थिक विबाध्यता पर आधारित तर्क सिरे से खारिज किया जा सकता है।

18. न्यायालय ने सबसे पहले सहमति अधिनिर्णय के मुद्दे पर प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया और यह भी देखा कि क्या यह कन्वेंशन के दायरे में आएगा। निर्विवाद रूप से, कन्वेंशन विशेष रूप से अभिव्यक्ति "मध्यस्थ अधिनिर्णय" को परिभाषित नहीं करता है। शब्द "अधिनिर्णय" जैसा कि कन्वेंशन के अनुच्छेद-झ से स्पष्ट होगा, मुख्य रूप से व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेदों की पृष्ठभूमि में दिए गए निर्णय के रूप में पहचाना जाता है। अनुच्छेद-झ में न केवल मध्यस्थ अधिनिर्णयों पर विचार किया गया है जो प्रत्येक मामले के लिए नियुक्त मध्यस्थों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं, बल्कि वे भी दिए जा सकते हैं जो संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद

V अधिनिर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन के विषय से संबंधित है। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार है:-

"अनुच्छेद V

1. जिस पक्ष के विरुद्ध यह लागू किया गया है, उसके अनुरोध पर अधिनिर्णय की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है, केवल तभी जब वह पक्ष सक्षम प्राधिकारी को प्रमाण प्रस्तुत करता है जहां मान्यता और प्रवर्तन की मांग की जाती है:

क . अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट समझौते के पक्षकार, उन पर लागू कानून के तहत, किसी असमर्थता के तहत थे, या उक्त समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके तहत पक्षों ने इसे किया है या उस पर कोई संकेत देने में विफल रहने पर, उस देश की कानून के तहत वैध नहीं है जहां अधिनिर्णय दिया गया था; या

ख. जिस पक्ष के खिलाफ अधिनिर्णय का आह्वान किया गया है, उसे मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला पेश करने में असमर्थ था; या

ग. अधिनिर्णय एक ऐसे अंतर से संबंधित है जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं विचारित है या नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल हैं, बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णय उन से अलग किए जा सकते हैं जो इस तरह प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो अधिनिर्णय के उस हिस्से को मान्यता दी जा सकती है और लागू किया जा सकता है जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णय शामिल हैं; या

घ. मध्यस्थता प्राधिकरण या मध्यस्थता प्रक्रिया की संरचना पक्षों के समझौते के अनुसार नहीं थी, या, इस तरह के समझौते में विफल होने पर, उस देश के कानून के अनुसार नहीं थी जहां मध्यस्थता हुई थी; या

ङ. अधिनिर्णय अभी तक पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं हुआ है, या देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपास्त या निलंबित कर दिया गया है, जिसमें या जिसके कानून के तहत, वह अधिनिर्णय दिया गया था।

19. जैसा कि उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट होगा, सहमति अधिनिर्णय को न तो विशेष रूप से इसके दायरे से बाहर रखा गया है और न ही अनुच्छेद V यह घोषित करता है कि पक्षकारगण के बीच समझौते के आधार पर लिया जाने वाला अधिनिर्णय कन्वेंशन के अंतर्गत नहीं आएगा। हालांकि यह सच हो सकता है कि संघीय गणराज्य जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा दिए गए सुझाव अंततः कन्वेंशन में शामिल किए जा रहे विशिष्ट प्रावधानों में तब्दील नहीं हुए, यह न्यायालय मौजूदा प्रश्न का उत्तर देने के प्रयोजनों के लिए इसे पूरी तरह से महत्वहीन स्थिति मानता है। इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कन्वेंशन "अधिनिर्णय" अभिव्यक्ति को परिभाषित करने से परहेज करता है। कन्वेंशन के विभिन्न अनुच्छेद स्पष्ट रूप से मध्यस्थता को एक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मान्यता देने का संकेत देते हैं जिसे पक्षकारगण के बीच विवाद उत्पन्न होने पर अपनाया जा सकता है। इस प्रकार, विवादों का अस्तित्व ही मध्यस्थता प्रक्रिया को शुरू करता है।

20. हालांकि, कन्वेंशन का कोई भी अनुच्छेद पक्षकारगण के समझौते पर पहुंचने के बाद मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। अस्तित्व में आने वाले सभी समझौतों को इस प्रकार एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया जा सकता है ताकि मौजूद विवादों को प्रभावी रूप से शांत किया जा सके। अधिनिर्णय में निपटान की शर्तों को अपनाना एक ऐसा

उपाय है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि यह पक्षकारगण को बांधता है, इसे कानून में लागू करने योग्य बनाता है और इस प्रकार पक्षकारगण के बीच एक निजी समझौते से परे और ऊपर जाता है।

21. जैसा कि एल्बटेलेकॉम और ट्रांसओसियन में संक्षेप में देखा गया है, जबकि मध्यस्थ कार्यवाही के बाहर किए गए समझौते को मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होने के बाद सहमति की शर्तों पर होने वाली रोक से अलग किया जा सकता है, कन्वेंशन के प्रावधानों को सहमति अधिनिर्णयों के लिए अनुपयुक्त मानने का कोई औचित्य नहीं है। एल्बटेलेकॉम और ट्रांसओसियन दोनों ही ऐसी मिसाल या सामग्री के अभाव की ओर इशारा करते हैं जो इस तर्क को समर्थन दे सकती है कि सहमति अधिनिर्णय एक अवधारणा है जो कन्वेंशन के लिए पूरी तरह से अलग है। इस प्रकार न्यायालय को एल्बटेलेकॉम और ट्रांसओसियन में व्यक्त दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण अपनाने का कोई औचित्य नहीं लगता है।

22. इस संबंध में संबोधित प्रस्तुतिकरण को सभी न्यायक्षेत्रों में मान्यता प्राप्त व्यापक सार्वजनिक नीति के आधार पर भी परीक्षण किया जा सकता है। निर्विवाद रूप से, 1996 का अधिनियम निपटान शर्तों के लिए विशिष्ट प्रावधानों को एक मध्यस्थ अधिनिर्णय का रूप देता है। वास्तव में, धारा 30(4) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि सहमत शर्तों पर एक मध्यस्थ अधिनिर्णय की स्थिति और प्रभाव विवाद के विषय पर किसी अन्य अधिनिर्णय के समान ही

होगा। उपधारा (4) अनिवार्य रूप से भारतीय न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांत की पुनरावृत्ति है कि सहमति पर तैयार की गई डिक्री समान शक्ति के साथ संचालित होती है और एक डिक्री के समान ही कायम होती है जो अंततः उचित प्रतिस्पर्धा के आधार पर तैयार की जा सकती है।

23. न्यायालय ने तब नोट किया कि पक्षकारों ने स्पष्ट शब्दों में आईसीसी मध्यस्थता नियमों द्वारा शासित हुई मध्यस्थता पर सहमत हुए थे। उन नियमों का अनुच्छेद 33 विशेष रूप से सहमति द्वारा अधिनिर्णय के विषय से संबंधित है। उक्त लेख यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> **"अनुच्छेद 33: सहमति से अधिनिर्णय**
> यदि अनुच्छेद 16 के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण को फ़ाइल प्रेषित होने के बाद पक्षकारगण समझौता करता हैं, यदि पक्षकारगण द्वारा अनुरोध किया गया है और यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसा करने के लिए सहमत है, तो निपटान को पक्षकारगण की सहमति से दिए गए अधिनिर्णय के रूप में दर्ज किया जाएगा।"

24. निपटान की शर्तों को शामिल करने वाले और सहमति पर दिए जाने वाले अधिनिर्णय की अवधारणा विभिन्न अन्य वैधानिक अधिनियमों और संस्थागत नियमों में भी प्रतिध्वनित होती है। निर्विवाद रूप से, यूनाइटेड किंगडम का 1996 का मध्यस्थता अधिनियम भी मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान समझौते पर पहुंचने वाले पक्षों पर विचार करता है और सहमति से अधिनिर्णय प्रदान करने में परिणत होता है। यह अंग्रेजी अधिनियम की धारा 51 से स्पष्ट है, जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"51 **समझौता।**

1. यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकार विवाद का निपटारा करते हैं, तो निम्नलिखित प्रावधान तब तक लागू होते हैं जब तक कि पक्षकारगण द्वारा अन्यथा सहमति न हो।
2. न्यायाधिकरण मूल कार्यवाहियों को समाप्त कर देगा और यदि पक्षकारगण द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है और न्यायाधिकरण द्वारा आपत्ति नहीं की जाती है, तो समझौता एक सहमत निर्णय के रूप में दर्ज किया जाएगा।
3. एक सहमत अधिनिर्णय में कहा जाएगा कि यह न्यायाधिकरण का एक अधिनिर्णय है और मामले के गुण-दोष पर किसी भी अन्य अधिनिर्णय के समान स्थिति और प्रभाव होगा।
4. अधिनिर्णयों से संबंधित इस भाग के निम्नलिखित प्रावधान (धारा 52 से 58) एक सहमत अधिनिर्णय पर लागू होते हैं।
5. जब तक पक्षकारगण ने मध्यस्थता की लागतों के भुगतान के मामले का भी निपटारा नहीं किया है, तब तक लागतों से संबंधित इस भाग के प्रावधान (धारा 59 से 65) लागू होते रहते हैं।"

25. निस्संदेह, **अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता 13 पर यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून** में भी सहमति पर दिए जाने वाले अधिनिर्णय के प्रावधान शामिल हैं। वास्तव में, अधिनियम 1996 की धारा 30 मॉडल कानून प्रावधानों की पुनरावृत्ति है। मॉडल कानून का अनुच्छेद 30 यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"अनुच्छेद 30. समझौता

1. यदि, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, पक्ष विवाद का निपटारा कर लेते हैं, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्यवाही समाप्त कर देगा और, यदि पक्षकारगण द्वारा अनुरोध किया जाता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण

द्वारा आपत्ति नहीं जताई जाती है, तो सहमत शर्तों पर मध्यस्थ अधिनिर्णय के रूप में निपटान को रिकॉर्ड किया जाएगा।

2. सहमत शर्तों पर एक अधिनिर्णय अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा और यह बताया जाएगा कि यह एक अधिनिर्णय है। इस तरह के अधिनिर्णय की स्थिति और प्रभाव मामले के गुण-दोष के आधार पर किसी भी अन्य अधिनिर्णय के समान ही होता है।"

26. जहां तक संस्थागत नियमों का सवाल है, **न्यायालय लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन 14** द्वारा बनाए गए मध्यस्थता नियमों के अनुच्छेद 26.9 पर ध्यान देता है, जो इस प्रकार है: -

"26.9 पक्षकारगण के विवाद के किसी भी अंतिम निपटान की स्थिति में, यदि पक्ष संयुक्त रूप से लिखित रूप में अनुरोध करते हैं (एक "सहमति अधिनिर्णय"), तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण निपटान को अभिलेख करते हुए एक अधिनिर्णय देने का निर्णय ले सकता है, बशर्ते कि हमेशा इस तरह के सहमति अधिनिर्णय में पहले से ही एक स्पष्ट बयान होगा कि यह पक्षकारगण के संयुक्त अनुरोध पर और उनकी सहमति से दिया गया अधिनिर्णय है। सहमति अधिनिर्णय में मध्यस्थता लागत या कानूनी लागत के संबंध में कारण या निर्धारण शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। यदि पार्टियां संयुक्त रूप से सहमति अधिनिर्णय का अनुरोध नहीं करती हैं, तो पक्षकारगण द्वारा एलसीआईए न्यायालय को लिखित पुष्टि पर कि अंतिम समझौता हो गया है, अनुच्छेद 24 और 28 के अनुसार किसी भी बकाया मध्यस्थता लागत के पक्षकारगण द्वारा भुगतान के अधीन, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को छुट्टी दे दी जाएगी और मध्यस्थता कार्यवाही एलसीआईए न्यायालय द्वारा समाप्त की जाएगी।

27. इसी तरह के प्रावधानों को नियम 55 के संदर्भ में **राज्यों और अन्य राज्यों के नागरिकों के बीच निवेश विवादों के निपटान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 15**

मध्यस्थता नियमों में शामिल किया गया है, जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **"नियम 55**
> **पक्षकारगण के समझौते द्वारा निपटान और विघटन**
>
> 1. यदि पक्ष न्यायाधिकरण को सूचित करते हैं कि वे कार्यवाही बंद करने के लिए सहमत हो गए हैं, तो न्यायाधिकरण कार्यवाही बंद करने पर ध्यान देते हुए एक आदेश जारी करेगा।
> 2. यदि पक्षकरगण अधिनिर्णय दिए जाने से पहले विवाद के निपटारे पर सहमत होते हैं, तो न्यायाधिकरण:
>
> क. यदि पक्ष ऐसा अनुरोध करते हैं, तो कार्यवाही को बंद करने का ध्यान रखते हुए एक आदेश जारी करेगा; या
>
> ख. यदि पक्ष अपने समझौते का पूरा और हस्ताक्षरित पाठ दाखिल करते हैं और अनुरोध करते हैं कि न्यायाधिकरण इस तरह के समझौते को एक अधिनिर्णय में शामिल करे, तो वे समझौते को एक अधिनिर्णय के रूप में दर्ज कर सकते हैं।
>
> (3) यदि न्यायाधिकरण अभी तक गठित नहीं हुआ है या यदि न्यायाधिकरण में कोई पद रिक्त है तो महासचिव अनुच्छेद (1) और (2)(क) में निर्दिष्ट आदेश जारी करेंगे।"

28. **एस. आई. ए. सी. नियमों** में **सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र** समान प्रावधानों को अपनाता है जैसा कि नियम 32.10 को पढ़ने से स्पष्ट होगा जो इस प्रकार है: -

> "32.10 किसी समझौते की स्थिति में, और यदि पक्ष ऐसा अनुरोध करते हैं, तो न्यायाधिकरण समझौते को दर्ज करते हुए एक सहमति अधिनिर्णय दे सकता है। यदि पक्षकारगण को सहमति अधिनिर्णय की आवश्यकता नहीं है, तो पक्षकारगण निबंधक को पुष्टि करेंगी कि एक समझौता हो गया है,

जिसके बाद न्यायाधिकरण को छुट्टी दे दी जाएगी और मध्यस्थता की लागतों के पूर्ण निपटान पर मध्यस्थता समाप्त हो जाएगी।"

29. **इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कमर्शियल आर्बिट्रेशन** ने अपने **"1958 न्यूयॉर्क कन्वेंशन की व्याख्या के लिए गाइड: न्यायाधीशों के लिए एक पुस्तिका"** में मध्यस्थ निर्णयों के अर्थ पर निम्नलिखित राय व्यक्त की है: -

"नतीजतन, निम्नलिखित मध्यस्थता निर्णय अधिनिर्णय के रूप में योग्य हैं:

- अंतिम अधिनिर्णय, अर्थात ऐसे अधिनिर्णय जो मध्यस्थता को समाप्त करते हैं। योग्यता के आधार पर सभी दावों से निपटने वाला अधिनिर्णय एक अंतिम अधिनिर्णय होता है।

ऐसा ही एक अधिनिर्णय है जो न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत विवाद पर उसके अधिकार क्षेत्र को नकारता है;

- आंशिक अधिनिर्णय, अर्थात ऐसे अधिनिर्णय जो दावों की ओर से अंतिम निर्णय देते हैं और शेष दावों को मध्यस्थता कार्यवाही के बाद के चरण के लिए छोड़ देते हैं। निर्माण मध्यस्थता में अतिरिक्त लागत के दावे से संबंधित एक अधिनिर्णय और दोषों के लिए नुकसान और कार्यवाही के बाद के चरण के लिए देरी के दावों को छोड़ना एक आंशिक अधिनिर्णय है (इस शब्द का उपयोग कभी-कभी निम्नलिखित श्रेणी के लिए भी किया जाता है, लेकिन बेहतर समझ के लिए, उन्हें अलग करना बेहतर है);
- प्रारंभिक अधिनिर्णय, जिन्हें कभी-कभी अंतर्वर्ती या अंतरिम अधिनिर्णय भी कहा जाता है, यानी ऐसे अधिनिर्णय जो पक्षों के दावों के निपटारे के लिए आवश्यक प्रारंभिक मुद्दे का निर्णय करते हैं, जैसे कि यह निर्णय कि क्या कोई दावा समय-वर्जित है, कौन सा कानून गुणों को नियंत्रित करता है, या क्या कोई दायित्व है।
- लागत पर अधिनिर्णय, अर्थात, मध्यस्थता लागत की राशि और आवंटन का निर्धारण करने वाले अधिनिर्णय;
- <u>सहमति अधिनिर्णय, अर्थात, विवाद के पक्षकारों के सौहार्दपूर्ण समाधान को दर्ज करने</u> वाले अधिनिर्णय।

30. **सहमति अधिनिर्णयों से** निपटने के दौरान **विदेशी मध्यस्थता अधिनिर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन पर यूएनसीआईटीआरएएल सचिवालय गाइड** इस प्रकार है: -

> *"घ. सहमति अधिनिर्णय*
> 36. पक्षकारगण के बीच समझौते की शर्तों को दर्ज करने वाले निर्णयों पर इसकी प्रयोज्यता के सवाल पर कन्वेंशन चुप है। सम्मेलन के दौरान, ऐसे निर्णयों पर कन्वेंशन को लागू करने का मुद्दा उठाया गया, लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया गया। रिपोर्ट किया गया मामला कानून इस मुद्दे को संबोधित नहीं करता है।"

जहां तक कानूनी स्थिति की समझ का संबंध है और जैसा कि उपरोक्त मार्गदर्शिका में निहित है, न्यायालय केवल यह देखता है कि वह अल्बटेलेकॉम और ट्रांसओसियन में दिए गए निर्णयों पर विचार नहीं करता है। वास्तव में, यह एक ऐसा पहलू था जिसे ट्रांसओसियन में निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने विधिवत नोट किया था।

31. रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल मध्यस्थता सिक्सथ एडिशन निम्नलिखित शब्दों में सहमति अधिनिर्णय की अवधारणा की व्याख्या करता है:-

> **"(ड.) सहमति अधिनिर्णय और बिना किसी अधिनिर्णय के कार्यवाही की समाप्ति**
> 9.34 राष्ट्रीय न्यायालयों में मुकदमेबाजी की तरह, एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के पक्ष अक्सर कार्यवाही के दौरान एक समझौते पर पहुंचते हैं। जहाँ ऐसा होता है, पक्षकार बस निपटान समझौते को लागू कर सकते हैं और इस प्रकार मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर सकते हैं।

इसका मतलब है कि पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र और शक्तियां समाप्त कर दी जाती हैं।

9.35 हालाँकि, कई मामलों में, पक्षों को यह वांछनीय लगता है कि समझौते की शर्तों को एक अधिनिर्णय में शामिल किया जाए। इसके कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी समझौते को लागू करने के लिए आगे के कदम उठाने के बजाय, किसी पक्ष के लिए भविष्य के दायित्व के दूसरे पक्ष द्वारा प्रदर्शन को लागू करना आमतौर पर आसान होता है, यदि बातचीत का दायित्व किसी अधिनिर्णय में निहित है (जिसके संबंध में न्यूयॉर्क कन्वेंशन की सहायता उपलब्ध हो सकती है)। सहमति अधिनिर्णय प्राप्त करने के अन्य कारणों में एक अधिनिर्णय के रूप में मध्यस्थता कार्यवाही का एक निश्चित और पहचान योग्य 'परिणाम' होने की वांछनीयता (विशेष रूप से जहां एक राज्य या राज्य एजेंसी शामिल है) शामिल है, जिसे कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त भुगतान प्राधिकरण को पारित किया जा सकता है। इस संदर्भ में, सहमति अधिनिर्णय पर मध्यस्थों के हस्ताक्षर पक्षकारगण द्वारा किए गए समझौते के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदन के एक उपाय को इंगित करते हैं। यह एक समझौते पर पहुंचने का निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार लोगों की राजनीतिक रूप से प्रेरित आलोचना का सामना करने में मदद कर सकता है।

9.36 जहां तक समझौता करने की क्षमता का संबंध है, बहुत कम या कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कई देश उन मामलों की अपनी परिभाषा के रूप में अपनाते हैं जो मध्यस्थता द्वारा समाधान करने में सक्षम हैं (यानी, ऐसे मामले जो 'मध्यस्थता' हैं) यह अवधारणा कि पक्ष मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद का उल्लेख कर सकते हैं जिसके संबंध में वे एक समझौते तक पहुंचने के हकदार हैं। इसका उलटा सच है: यदि पक्ष किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के हकदार हैं, तो वे विवाद के संबंध में समझौता करने के भी हकदार हैं।

9.37 राष्ट्रीय कानून, या अंतरराष्ट्रीय या मध्यस्थता के संस्थागत नियमों द्वारा इस आशय का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है कि, एक बार मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद, पक्षकारगण समझौते से उन्हें समाप्त नहीं कर सकती हैं। इसके विपरीत, किसी समझौते का हमेशा स्वागत किया जाता है, और यह संभव हो सकता है कि इसे एक सहमत अधिनिर्णय में दर्ज किया जाए, मॉडल कानून का अनुच्छेद 30 ऐसे सहमत अधिनिर्णय का प्रावधान करता है; यूएनसीआईटीआरएएल नियमों का अनुच्छेद 36(1) एक आदेश या अधिनिर्णय द्वारा निपटान को दर्ज करने का प्रावधान करता है:

यदि, अधिनिर्णय दिए जाने से पहले, पक्षकार विवाद के निपटारे पर सहमत होते हैं, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण या तो मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश जारी करेगा या, यदि पक्षों द्वारा अनुरोध किया जाता है और न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो सहमत शर्तों पर मध्यस्थता अधिनिर्णय के रूप में निपटान दर्ज करेगा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस तरह के निर्णय के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

आई. सी. सी. नियमों में अनुच्छेद 32 में एक समान प्रावधान है, यदि अनुच्छेद 13 के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण को फाइल भेजे जाने के बाद पक्षकार किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं, तो समझौता पक्षों की सहमति से किए गए अधिनिर्णय के रूप में दर्ज किया जाएगा, यदि पक्षों द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है और यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसा करने के लिए सहमत होता है। 'विल' शब्द अनिवार्य है और सहमति अधिनिर्णय में किसी भी समझौते को दर्ज करने के लिए एक विस्मरण का सुझाव देता है। हालाँकि, यह आवश्यकताओं द्वारा योग्य है कि पक्षों को इस तरह के अधिनिर्णय का अनुरोध करना चाहिए और न्यायाधिकरण को इसके लिए सहमत होना चाहिए। यह इंगित करता है कि यूएनसीआईटीआरएएल और आईसीसी नियमों के तहत, दोनों पक्षों या न्यायाधिकरण के लिए सहमति अधिनिर्णय देने का कोई दायित्व नहीं है।

9.38 हालाँकि, पक्षकार जो भी नियमों के तहत कार्यवाही कर रहे हैं, पक्षकारगण के बीच हुए किसी भी समझौते के बारे में मध्यस्थ न्यायाधिकरण (और उपयुक्त मध्यस्थता संस्थान, यदि कोई शामिल है) को सूचित करना शालीनता का एक सामान्य कार्य होगा, विशेष रूप से यदि बैठकें या सुनवाई पहले ही हो चुकी हैं। सामान्य शालीनता की माँगों को पूरा करने के लिए ठोस वित्तीय कारण भी हो सकते हैं। पहला, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को किसी समझौते के बारे में सूचित करने से यह सुनिश्चित होगा कि इसमें अतिरिक्त शुल्क और खर्च (किसी भी रद्द करने के शुल्क के अलावा जो सहमत हो सकते हैं) नहीं होंगे, दूसरा, इस तरह की अधिसूचना से शुल्क और खर्चों को कवर करने के लिए किए गए अग्रिम भुगतान की वापसी हो सकती है, क्योंकि यदि मामले को बिना सुनवाई के निपटाया गया है तो वास्तविक लागत अपेक्षा से कम हो सकती है। तीसरा, जैसा कि पहले से ही स्पष्ट किया गया है, जब भविष्य के प्रदर्शन का कोई तत्व हो तो निपटान की शर्तों को लागू करने योग्य रूप में रखना वांछनीय है। हालाँकि अधिकांश समझौतों में सहमत शर्तों का तत्काल कार्यान्वयन शामिल होता है, फिर भी इसके लिए प्रावधान होना असामान्य नहीं है।

9.39 एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की भूमिका के बारे में कभी-कभी एक सवाल उठता है जिसे पक्षों द्वारा एक गैरकानूनी कार्य के प्रदर्शन का आदेश देते हुए सहमति अधिनिर्णय देने का अनुरोध किया जाता है। उदाहरण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित दवा का निर्माण, या निषिद्ध पदार्थों की ये तस्करी या-शायद अधिक यथार्थवादी-एक समझौता हो सकता है जो स्पष्ट रूप से प्रासंगिक प्रतिस्पर्धा या अविश्वास कानूनों का उल्लंघन करता है। एक समय में, नियमों के विभिन्न सेट (1998 से पहले आईसीसी नियमों सहित) न्यायाधिकरण को बिना किसी विवेक के छोड़ देते थे, लेकिन आधुनिक नियम और कानून मध्यस्थ न्यायाधिकरण को सहमति अधिनिर्णय देने से इनकार करने की अनुमति देते हैं।"

32. परिणामस्वरूप, न्यायालय इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कन्वेंशन के दायरे में नहीं आने वाले सहमति अधिनिर्णय का तर्क अस्वीकृति के योग्य है। पक्षकारगण के बीच होने वाले

समझौते के आधार पर अधिनिर्णय दिए जाने की संभावना को स्वीकार करने के लिए सभी न्यायक्षेत्रों में स्पष्ट रूप से एकमतता दिखाई देती है। एल्बमटेलेकॉम और ट्रांसओसियन के निर्णयों में एकमात्र अंतर मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू होने से पहले किए गए समझौतों और उसके दौरान किए जा सकने वाले समझौतों का है। इस प्रकार यह मानने का कोई कानूनी औचित्य प्रतीत नहीं होता है कि सहमति अधिनिर्णय या तो मान्यता प्राप्त नहीं हैं या अप्रवर्तनीय हैं। विभिन्न न्यायक्षेत्रों में इस विषय पर एकमत राय के आलोक में और जिसे 1996 के अधिनियम में विधिवत अपनाया और शामिल किया गया है, न्यायालय ने पाया कि अधिनिर्णय को संभवतः भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं कहा जा सकता है।

33. न्यायालय इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण स्पष्ट रूप से समझौते को अधिनिर्णय का दर्जा देने के लिए आगे बढ़ने से पहले उसे प्रदान करता प्रतीत होता है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने विधिवत एक मसौदा अधिनिर्णय प्रसारित किया था और संबंधित पक्षों की टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। केवल एक बार उन प्रतिक्रियाओं के प्राप्त होने के बाद ही अधिनिर्णय की औपचारिक घोषणा की गई। प्रत्यर्थीगण ने निर्विवाद रूप से 04 सितंबर 2020 के अपने ईमेल के माध्यम से न्यायाधिकरण को निपटान के संदर्भ में आगे बढ़ने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी। इस संबंध में उठाई गई आपत्तियां उपरोक्त कारणों से खारिज कर दी गई हैं।

34. इसके बाद न्यायालय को आर्थिक विबाध्यता के तर्क पर विचार करना पड़ता है। जैसा कि श्री मेहता ने सही तर्क दिया था, प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही के सभी चरणों में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अधिवक्तागण द्वारा उचित रूप से प्रतिनिधित्व किया गया था। तथ्य यह है कि पक्षकारगण द्वारा स्वतंत्र कानूनी राय प्राप्त करने के बाद समझौते की शर्तें तैयार की गईं, यह एक ऐसा तथ्य है जो निपटान समझौते में ही स्पष्ट रूप से दर्ज है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण भी निपटान समझौते को अपनाने और इसे अधिनिर्णय का रूप देने

की कार्यवाही से पहले पक्षों की राय और सहमति प्राप्त करने के लिए सतर्क था। यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो जाता है कि वर्तमान आपत्तियों को दाखिल करने से पहले किसी भी स्तर पर प्रत्यर्थीगण ने आर्थिक विबाध्यता या जबरदस्ती की दलील नहीं दी थी।

35. विबाध्यता की अवधारणा और अनुबंधों के निर्माण के साथ इसके संबंध को प्रिवी काउंसिल ने **पाओ ऑन और लाउ यिउ लॉन्ग**, में अपने निर्णय में निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट रूप से समझाया था: -

> "तीसरा **सवाल**
>
> विबाध्यता, चाहे वह किसी भी रूप में हो, सहमति को ख़राब करने के लिए इच्छाशक्ति का विबाध्यता है। उनके आधिपत्य ऑक्सिडेंटल वर्ल्डवाइड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बनाम स्किब्स ए/एस अवंती [1976] 1 लॉयड्स प्रतिनिधि 293, 336 में केर जे की टिप्पणी से सहमत हैं कि एक संविदात्मक स्थिति में व्यावसायिक विबाध्यता पर्याप्त नहीं है। इसमें कुछ ऐसे कारक अवश्य मौजूद होने चाहिए "जिसे कानूनन उसकी इच्छा के प्रति जबरदस्ती माना जा सकता है ताकि उसकी सहमति को नष्ट किया जा सके।" यह अवधारणा बार्टन बनाम आर्मस्ट्रांग [1976] ए.सी. 104, 121 में लॉर्ड विल्बरफोर्स और ग्लैसडेल के लॉर्ड साइमन द्वारा इस बोर्ड के निर्णय में कही गई बातों के अनुरूप है - जिन टिप्पणियों के साथ बहुमत का निर्णय सहमत प्रतीत होता है। यह निर्धारित करने में कि क्या वसीयत के साथ जबरदस्ती की गई थी कि कोई सच्ची सहमति नहीं थी, यह जांचना महत्वपूर्ण है कि क्या जिस व्यक्ति पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया है उसने विरोध किया था या नहीं; क्या, उस समय कथित तौर पर अनुबंध करने के लिए उसे मजबूर किया गया था, उसने ऐसा किया था या उसके लिए पर्याप्त कानूनी उपाय जैसा कोई वैकल्पिक रास्ता खुला नहीं था; क्या उसे स्वतंत्र रूप से सलाह दी गई थी; और क्या अनुबंध में प्रवेश करने के बाद उसने इससे बचने के लिए कदम उठाए। ये सभी मामले, जैसा कि मास्केल बनाम हॉर्नर [1915] 3 के.बी. 106 में माना गया था, यह निर्धारित करने में प्रासंगिक हैं कि उसने स्वेच्छा से कार्य किया या नहीं।

वर्तमान मामले में नीचे दिए गए न्यायाधीशों के बीच सर्वसम्मति है कि पहले प्रतिवादी की वसीयत पर कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। अपील न्यायालय में विचारण न्यायाधीश का निष्कर्ष (पहले ही उद्धृत) कि पहले प्रतिवादी ने मामले पर पूरी तरह से विचार किया, मुकदमेबाजी से बचने का विकल्प चुना, और यह राय बनाई कि गारंटी देने में जोखिम वास्तविक से अधिक स्पष्ट था, को बरकरार रखा गया। संक्षेप में, व्यावसायिक विबाध्यता था, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं थी। भले ही इस बोर्ड का निपटारा किया गया हो, जो एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए नहीं है, यह तथ्य के इस प्रश्न पर नीचे दिए गए न्यायाधीशों की राय को प्रतिस्थापित नहीं करेगा।

इसलिए, बोर्ड के लिए इस सवाल की जांच शुरू करना अनावश्यक है कि क्या अंग्रेजी कानून विबाध्यता की एक श्रेणी को मान्यता देता है जिसे "आर्थिक विबाध्यता" के रूप में जाना जाता है। लेकिन, चूंकि इस अपील में प्रश्न पर पूरी तरह से तर्क दिया गया है, इसलिए उनके आधिपत्य बहुत संक्षेप में उस दृष्टिकोण को इंगित करेंगे जो उन्होंने बनाया है। आम कानून में आर्थिक मजबूरी के तहत भुगतान किया गया पैसा एस्टली बनाम रेनॉल्ड्स (1731) 2 स्ट्रेट के पैसे के लिए कार्रवाई में वसूल किया जा सकता है। 915. मजबूरी ऐसी होनी थी कि पक्षकार "अपनी इच्छा का प्रयोग करने की स्वतंत्रता" से वंचित हो गई (देखें पृष्ठ 916)। हालाँकि, यह संदिग्ध है कि क्या आम कानून में व्यक्ति पर विबाध्यता के अलावा कोई भी विबाध्यता अनुबंध को अमान्य करने के लिए पर्याप्त है: सेकंड ब्लैकस्टोन की टिप्पणियाँ, पुस्तक 1, 12वां संस्करण पीपी 130-131 और स्केट बनाम बीले (1841) 11 संस्करण और ई 983. अमेरिकी कानून (विलिस्टन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, तीसरा संस्करण) अब मानता है कि आर्थिक विबाध्यता के आधार पर किसी अनुबंध को टाला जा सकता है। हालाँकि, इस तरह के विबाध्यता के लिए कथित व्यावसायिक विबाध्यता ऐसा होना चाहिए कि पीड़ित ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुबंध में प्रवेश किया हो, उसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता खुला न हो, और विबाध्यता डालने वाले पक्ष द्वारा उसे जबरदस्ती कृत्यों का सामना करना पड़ा हो। : विलिस्टन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, तीसरा संस्करण, खंड 13 (1970), खंड 1603। अमेरिकी

न्यायाधीश उपलब्ध वैकल्पिक उपाय की प्रभावशीलता, विरोध के तथ्य या अनुपस्थिति, स्वतंत्र सलाह की उपलब्धता, प्राप्त लाभ और जिस गति से पीड़ित ने अनुबंध से बचने की मांग की है, जैसे साक्ष्य संबंधी मामलों पर बहुत ध्यान देते हैं। हाल ही में दो अंग्रेजी न्यायाधीशों ने माना है कि व्यावसायिक विबाध्यता विबाध्यता हो सकता है जिसके विबाध्यता से अनुबंध रद्द हो सकता है: ऑक्सिडेंटल वर्ल्डवाइड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बनाम स्किब्स ए/एस अवंती [1976] 1 लॉयड प्रतिनिधि में केर जे.। 293 और नॉर्थ ओसियन शिपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में मोकाटा जे. [1979]3 डब्लूएलआर 419। दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि विबाध्यता ऐसा होना चाहिए कि अनुबंध के लिए पीड़ित की सहमति उसकी ओर से एक स्वैच्छिक कार्य न हो। उनके आधिपत्य के विचार में, आर्थिक विबाध्यता को एक ऐसे कारक के रूप में मान्यता देने में सिद्धांत के विपरीत कुछ भी नहीं है जो अनुबंध को अमान्य कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी मान्यता का आधार यह हो कि यह इच्छाशक्ति के विबाध्यता के बराबर होना चाहिए, जो सहमति को नष्ट कर देता है। यह दिखाया जाना चाहिए कि किया गया भुगतान या किया गया अनुबंध स्वैच्छिक कार्य नहीं था।"

36. “पाओ ऑन में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार "विबाध्यता" को एक अनुबंध से पीछे हटने के आधार के रूप में उठाया जा सकता है, बशर्ते कि एक पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम हो कि जबरदस्ती इस हद तक थी जिससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि अनुबंध के लिए पीड़ित की सहमति स्वैच्छिक कार्य नहीं थी। यह अंततः पीड़ित का दायित्व है कि वह यह साबित करे कि जबरदस्ती ने स्पष्ट रूप से सहमति को धूमिल कर दिया है।

37. यह पहलू **सारा इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम रिझाओ स्टील होल्डिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड** में हमारे न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश के विचार के लिए भी आया था, जहां आर्थिक

दबाव के सिद्धांत को जबरदस्ती के तत्वों के रूप में समझाया गया था और इसे सहमति को धूमिल करने के लिए पेश किया गया था। सारा इंटरनेशनल हमारे उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त महत्व रखता है क्योंकि वह भी ऐसा मानता है कि पक्ष पहले उपलब्ध अवसर पर आर्थिक दबाव की आपत्ति उठाने में विफल रहे हैं या जहां यह दिखाया गया है कि उचित विचार-विमर्श और कानूनी सलाह प्राप्त करने पर सहमति बनी थी, आर्थिक दबाव का आरोप टिक नहीं पाएगा। न्यायालय उपरोक्त निर्णय से निम्नलिखित अंशों का उल्लेख करना उचित समझता है: -

> **"20.** श्री वशिष्ठ का मानना है कि यदि मामले के तथ्य इस तरह के निर्णय को उचित ठहराते हैं तो आर्थिक दबाव के आधार पर वाणिज्यिक अनुबंधों से बचा जा सकता है। वह बताते हैं कि डबल डॉट फाइनेंस लिमिटेड बनाम गोयल एमजी गैसेज लिमिटेड, 2005 (117) डीएलटी 330 में इस न्यायालय ने माना कि कोई आर्थिक दबाव नहीं था और उक्त आदेश को गोयल एमजी गैसेस लिमिटेड बनाम डबल डॉट फाइनेंस लिमिटेड, 2009 (2) एआरबी एलआर, 655 में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखा गया था।
>
> ***21.*** वह आगे बताते हैं कि यूनिकोल बॉटलर्स लिमिटेड बनाम ढिल्लन कूल ड्रिंक्स, एआईआर 1995 दिल्ली 25, (अनुच्छेद 31 से 37) में, आर्थिक दबाव की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की गई थी और इसे मान्यता दी गई थी, लेकिन एक बार फिर न्यायालय को उस मामले के तथ्यों में कोई आर्थिक दबाव नहीं मिला। उक्त मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा, "...दबाव/जबरदस्ती और असमान सौदेबाजी की शक्ति के प्रश्न से निपटते समय व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र इच्छा के प्रश्न से चिंतित होता है, यानी क्या पक्षकारगण ने स्वतंत्र इच्छा के साथ समझौते में प्रवेश नहीं किया है?" यह वादी ही है जिसने यह सवाल उठाया है कि उसकी इच्छा पर प्रतिवादियों का प्रभुत्व है और इसलिए, वह एक स्वतंत्र एजेंट नहीं है। अत: वादी परीक्षणाधीन है। यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरक समझौते में

प्रवेश करते समय वादी ने स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग किया था या नहीं। इस प्रयोजन के लिए कई कारक हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे हैं -

1. क्या वादी ने समझौते से पहले या तुरंत बाद विरोध किया था?

2. क्या वादी ने अनुबंध से बचने के लिए कोई कदम उठाए?

3. क्या वादी के पास कार्रवाई का कोई वैकल्पिक तरीका या उपाय था?यदि हां, तो क्या वादी ने इसको आगे बढ़ाया या इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया?

4. क्या वादी ने स्वतंत्र सलाह का लाभ दिया?"

22. वादी के विद्वान अधिवक्ता और न्यायमित्र को सुनने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि आर्थिक दबाव के दावे के आधार पर किसी अनुबंध को सफलतापूर्वक टालने के लिए आवश्यक तत्व हैं: -

क. वादी के विद्वान अधिवक्ता और न्यायमित्र को सुनने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि आर्थिक दबाव के दावे के आधार पर किसी अनुबंध को सफलतापूर्वक टालने के लिए आवश्यक तत्व हैं: दबाव जो अवैध है;

ख. पीड़ित पर इसका प्रभाव यानी कि दबाव दावेदार को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए;

ग. उचित विकल्प की कमी अर्थात दबाव का व्यावहारिक प्रभाव यह था कि पीड़ित के लिए मजबूरी या व्यावहारिक विकल्प की कमी थी।

23. आर्थिक विबाध्यता के मुद्दे पर निर्णय लेते समय न्यायालय को यह भी ध्यान रखना होता है कि क्या पीड़ित द्वारा विवादित अनुबंध से पहले या उसके तुरंत बाद विरोध किया गया था और क्या पीड़ित को स्वतंत्र सलाह का लाभ मिला था।

24. यह उल्लेख करना उचित है कि डी. *एस. एन. डी.* सबसी *लिमिटेड बनाम पेट्रोलियम जियो सर्विसेज* ए. एस. ए. 2000 डब्ल्यू. एल. 1741490, न्यायालय ने कहा कि- अवैध विबाध्यता *को सामान्य वाणिज्यिक सौदेबाजी के विबाध्यताओं के खुरदरे और गिरने से अलग किया जाना चाहिए।"*

25. सी. *टी. एन. कैश एंड कैरी* लिमिटेड *बनाम गैलहर लिमिटेड* [1994] 4 ऑल ई. आर. 714, न्यायालय ने कहा कि यह तथ्य कि प्रतिवादी सिगरेट

> के लोकप्रिय ब्रांडों के एकमात्र वितरक के रूप में एकाधिकार की स्थिति में था, अप्रासंगिक था और जो अन्यथा विबाध्यता में नहीं था उसे विबाध्यता में परिवर्तित नहीं कर सकता था क्योंकि सामान्य कानून वाणिज्यिक लेन-देन में सौदेबाजी की शक्ति की असमानता के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता है। मामले में स्टेन एलजे ने कहा,- -मैं यह भी आसानी से स्वीकार करता हूं कि यह तथ्य कि प्रतिवादियों ने वैध तरीकों का इस्तेमाल किया है, इस मामले को आर्थिक दबाव के सिद्धांत के दायरे से नहीं हटाता है..... दूसरी ओर, गोफ और जोन्स द लॉ ऑफ रिस्टीट्यूशन (तीसरा संस्करण, 1986) पृष्ठ 240 में पाया गया कि अंग्रेजी न्यायालयों ने बुद्धिमानी से किसी भी सामान्य सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है कि कुछ शर्तों को छोड़कर, दूसरे के साथ अनुबंध न करने की धमकी, विबाध्यता के समान हो सकती है... ..... संरक्षित संबंधों के क्षेत्र के बाहर, और विशुद्ध रूप से व्यावसायिक संदर्भ में, यह एक अपेक्षाकृत दुर्लभ मामला हो सकता है जिसमें 'वैध कार्य विबाध्यता' स्थापित किया जा सकता है। और विबाध्यता स्थापित करना विशेष रूप से कठिन हो सकता है यदि प्रतिवादी ने ईमानदारी से माना कि उसकी मांग वैध थी। कानून की इस जटिल और बदलती शाखा में मैं जानबूझकर "कभी नहीं" कहने से बचता हूँ। लेकिन जैसा कि कानून की स्थिति है, मैं संतुष्ट हूं कि इस मामले में प्रतिवादीगण का आचरण विबाध्यता डालने जैसा नहीं था।"

38. हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों और जो यहाँ ऊपर देखे गए हैं, उन पर गौर करने से यह न्यायालय इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आर्थिक दबाव और जबरदस्ती का आरोप स्पष्ट रूप से एक बाद का विचार है और सहमति अधिनिर्णय की शर्तों से पीछे हटने का एक व्यर्थ प्रयास है। उपरोक्त सभी कारणों से उक्त आपत्ति विफल हो जाती है और अस्वीकार कर दी जाती है। इस प्रकार न्यायालय इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधिनिर्णय स्पष्ट

रूप से लागू करने योग्य है और अधिनियम 1996 की धारा 48 में शामिल किसी भी नकारात्मक शर्त का उल्लंघन नहीं करता है।

39. विदेशी अधिनिर्णय की मान्यता और प्रवर्तन पर आपत्तियां खारिज कर दी गईं। निष्पा.आ. (मूल पक्ष) 3525/2022 को अब अधिनिर्णय के निष्पादन के लिए आगे के कदम उठाने के लिए उपयुक्त न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

40. दिनांक 27.07.2023 को रोस्टर न्यायपीठ के समक्ष सूची प्रस्तुत करें।

न्या. यशवंत वर्मा

30 मई, 2023/एसयू

Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*